लातों के भूतबातों से नहीं मानते-

नेपाल प्राचीन काल से ही अविच्छिन्न रूप से अनुप्राणित, प्रभावित और संचालित हिन्दू राष्ट्र रहा है। विश्व का यह प्रमुख हिन्दू राष्ट्र नेपाल आज अपने भविष्य के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। यदि समय रहते सही दिशा में निर्णय नहीं हुआ तो न हिन्दुत्व का भला होगा न नेपाल का और न ही भारत सहित सम्पूर्ण हिन्दू जगत् का। मई, 2006 में भारत के सक्रिय सहयोग से नेपाल नरेश ने नेपाल के सात दलों के जिस गठबंधन को देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सत्ता सौंपी थी वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित करने में पूर्णतया असफल रही और माओवादियों के दबाव में निरन्तर अवैधानिक निर्णय लेती जा रही है। 18 मई, 2006 को माओवादियों के ही दबाव में आकर एक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल को जबरन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यही नहीं जो ''राजतंत्र'' नेपाल की एकता और अखण्डता के प्रतीक के रूप में पिछले 250 वर्षों से अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका को निभाता आ रहा है, प्रयोजन विशेष के लिए बहाल की गई संसद द्वारा जिस अपमानजनक एवं अवैधानिक तरीके से उस राजतंत्र के प्रतीक नेपाल नरेश के अधिकारों में कटौती की गई वह भी कम आश्चर्यजनक नहीं। माओवादी यह बात जानते हैं कि नेपाल के अन्दर राजतंत्र शक्ति का एक प्रमुख केन्द्र है। राजतंत्र के रहते माओवादियों की अराजकता और उच्छृंखलता सरेआम नहीं हो सकती, इसलिए लोकतंत्र बहाली के नाम पर राजतंत्र को समाप्त करना और फिर येनकेन प्रकार-ेण सत्ता पर काबिज होना उनका एकमात्र लक्ष्य है। यह स्थिति नेपाल की एकता एवं अखण्डता के लिए खतरे की घंटी है ही, नेपाल के तराई क्षेत्र में उत्पन्न मधेशी आन्दोलन इसी का दुष्परिणाम भी है। पिछले 12 वर्षों में माओवादी हिंसा में नेपाल के अन्दर 15,000 से अधिक निर्दोष नागरिक एवं सुरक्षा बलों के जवान मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए और विकास की प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित हुई। इसी दौरान 7 से

8 हजार माओवादी उग्रवादी भी मारे गए। इस सबका आश्चर्यजनक पहलू यह है कि विश्व मंच पर परस्पर युद्धरत ईसाई, इस्लामी और कम्युनिष्ट अलगाववादी ताकतें नेपाल के वर्तमान स्वरूप को नष्ट करने तथा हिन्दुत्वनिष्ठ शक्तियों के खिलाफ परस्पर सहयोग करते हुए बन्दरबांट में लगी हैं। यदि इन ताकतों का उभार इसी प्रकार रहा तो यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथसाथ राष्ट्रीय - एकता और अखण्डता के लिए भी गम्भीरचुनौती होगी। जिन माओवादियों को जनतंत्रवादी मानकर भारत सरकार और भारत के साम्यवादी दल समर्थन कर रहे हैं, आखिर वे माओवादी कब से जनतंत्रवादी बन गए हैं? जिनका मूलभूत सिद्धान्त ही बंदूक की नोक पर सत्ता प्राप्त करना हो आखिर उनसे किन लोकतांत्रिक मूल्यों के स्थापना की बात की जा रही है। सच तो यह है कि माओवादियों का न तो लोकतंत्र में विश्वास है न किसी प्रकार की मानवीय संवेदना ही उनके अन्दर है। माओवादी सरगना प्रचण्ड का यह बयान लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनका दृष्टिकोण उजागर करता है, जिसमें उन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि "अगर जनता ने उन्हें मतदान में नहीं चुना तो वह जबरन सत्ता पर कब्जा कर लेंगे"। यह न केवल उनके तानाशाही व्यवहार को बताता है अपितु दोहरे चरित्र को भी प्रदर्शित करता है। आज भी नेपाल में माओवादी गुण्डों ने अपनी लूटपाट, हिंसा, जबरन वसूली, तोड़फोड़ आदि बन्द नहीं किया है। यह अत्यन्त दुःखद है कि एक ओर नेपाल की सरकार ने शाही सेना को बैरकों में बन्द किया हुआ है, सिविल पुलिस के पास कोई हथियार नहीं, बावजूद इसके माओवादी गुण्डे सरेआम हथियारबन्द गिरोहों की तरह लूटपाट, बलात्कार एवं हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए सीधेसीधे जिम्मेदार माओवादी - सरगना प्रचण्ड आज नेपाल नरेश को अपदस्थ कर नेपाल का राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहा है। दुर्भाग्य से अगर उसका यह सपना सच होता है तो यह भारत जैसे देश के लिए अत्यन्त खतरनाक होगा। नेपाल के अन्दर आज के दिन कोई संवैधानिक सत्ता नहीं रही। सात दलों की गठबंधन सरकार माओवादियों के सामने

शिखण्डी साबित हुई है। यही कारण है कि नेपाल के अन्दर संविधान सभा के चुनाव कराने के नाम पर भारत सरकार के सहयोग से जो नौटंकी प्रारम्भ हुई है, भारत सरकार के द्वारा इसके लिए जो सहायता प्रदान की जा रही है, वह सहायता धीरेधीरे माओवादियों के हाथ में पहुँच रही है।-

माओवादियों के हाथों में पहुँचकर पुनः यही सहायता भारत के नक्सलवादियों को प्राप्त हो रही है। नेपाल के अन्दर चल रही इन माओवादी गतिविधियों के कारण सर्वत्र अराजकतापूर्ण वातावरण फैला हुआ है और लोगों की जानमाल ही नहीं देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन माओवादी उग्रवादियों से आज मात्र नेपाल ही त्रस्त नहीं है। इनका सम्बन्ध भारत के अन्दर हिंसा में लिप्त विभिन्न नक्सलवादी उग्रवादी संगठनों से, पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आईके साथ ही भारत में सक्रिय कुख्यात आतंकवादी .आई.एस. संगठनों उल्फा, लिट्टे, लश्कर-ए-तैयबा, जैशमोहम्मद-ए-, सिमी, हूजी आदि से भी है। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल की घटनाओं से भारत भी प्रभावित रहेगा। आज जिस प्रकार नेपाल के अन्दर सात दलों का गठबंधन माओवादियों के सामने शिखण्डी साबित हुआ है उसके कारण भारत के अन्दर भी नक्सलवादी हिंसा बढ़ी हैं, उल्फा सहित अन्य सभी आतंकवादी संगठनों का उपद्रव भी बढ़ा है। यह मात्र और मात्र इसलिए बढ़ा है क्योंकि नेपाल के अन्दर माओवादियों की हिंसा और उद्दण्डता पर भारत सरकार मौन है और भारत के साम्यवादियों का पूरा समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है। इसी कारण नेपाल से भारत तक अराजकता और हिंसा को प्रसारित करके हम सबके सामने अभूतपूर्व संकट खड़ा किया जा रहा है। नेपाल की बहुसंख्यक जनता यद्यपि आज भी हिन्दू राष्ट्रीयता और हिन्दू राजतंत्र के प्रति आस्थावान है किन्तु, खुलेआम घूम रहे माओवादी गुण्डों की अराजकता से वह सहमी हुई है। यह स्थिति नेपाल ही नहीं भारत की एकता और अखण्डता की दृष्टि से भी शुभ नहीं कही जा सकती। फिलहाल नेपाल की वर्तमान स्थिति में माओवाद पर ''लातों के भूतबातों से नह-ीं मानते'' जैसी उक्ति ही चरितार्थ हो सकती है।

भारत के धर्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि तमाम दृष्टियों से आत्मीय राष्ट्र नेपाल का अस्तित्व जिस हिन्दुत्वनिष्ठ स्वरूप पर टिका है, उसके इस हिन्दू चरित्र, इतिहास और स्वरूप के विरुद्ध किसी अभियान को न केवल विफल बनाया जाना चाहिए अपितु संवैधानिक राजतंत्र के अन्तर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने और माओवादी ताकतों की आड़ में सक्रिय हो रही इस्लामी एवं ईसाई अलगाववादी ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत जैसे सहोदर पड़ोसी का हस्तक्षेप आवश्यक एवं समीचीन भी है। हमारे लिए ऐसा करना केवल नेपाल के हिन्दू राष्ट्र के स्वरूप की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि नेपाल के अन्दर सक्रिय आतंकवादी ताकतें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के इशारे पर संचालित हैं। वे अपने मकसद में सफल हुए तो यह भारत के लिए नितान्त घातक होगा और भारत की नेपाल से लगी 1751 कि .मी. लम्बी उत्तरी सीमा पर एक और तिब्बत या कश्मीर खड़ा होगा।